छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र

त्रैमासिक समाचार पत्रिका

अंक - 15 (जनवरी - मार्च 2021)

ईमेलः- chhattisgarh.sccc@gmail.com वेबसाइटः- www.cgclimatechange.com

मुख्य सम्पादक की कलम से.....

सम्माननीय पाठक,

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक न्यूजलेटर के 14वें अंक में आप सभी का स्वागत है। कोविड 19 महामारी के फलस्वरूप उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद केंद्र अपनी सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से जारी रखने का प्रयास कर रहा है।

जलवायु परिवर्तन पर राज्य की कार्य योजना के पुनरीक्षण का कार्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देश के आधार पर किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए एवं पुनरीक्षण कार्य में संलग्न विशेषज्ञों की अनुशंसा के आधार पर पुनरीक्षित SAPCC में 03 नये विभाग यथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास तथा आपदा प्रबंधन को भी शामिल किया गया है।

जलवायु परिवर्तन पर राज्य की कार्य योजना के पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतिम चरण के रूप में, सभी सम्बंधित विभागों के प्रतिनिधियों के साथ एक प्राथमिकता निर्धारण कार्यशाला का आयोजन दिनांक 25/02/2021 को किया गया ताकि प्रमुख अनुकूलन और शमन उपायों का चयन किया जा सके।

इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किये जा रहे उल्लेखनीय कार्यों को इस अंक में शामिल किया गया है।

हम इस न्यूजलेटर के आगामी अंकों को बेहतर बनाने के लिये आपके सुझावों का स्वागत करते हैं ।

(सुधीर कुमार अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना)
तथा नोडल अधिकारी, राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र
अरण्य भवन, नवा रायपुर

विषय–वस्तु

- छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के पुनरीक्षण हेतु प्राथमिकता कार्यशाला का आयोजन
- छत्तीसगढ़ में देश के तीन चौथाई से अधिक लघु वनोपजों का संग्रहण
- नरवा विकास योजना – वन क्षेत्रों में भू–जल संरक्षण के बड़े तादाद में हो रहे कार्य
- राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'गोधन न्याय योजना' को मिला स्कॉच गोल्ड अवार्ड
- क्या आप जानते हैं ?
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित किया
- केरल के एनएस राजप्पन जो प्रतिदिन वेम्बनाड झील की सफाई करते हैं
- विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर भारत को मिला पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केन्द्र
- समाचार शीर्षक

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के पुनरीक्षण हेतु प्राथमिकता कार्यशाला का आयोजन

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा 2019 में "जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना के पुनरीक्षण के लिए एक सामान्य रूपरेखा" के रूप में SPACC के पुनरीक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। SAPCC के पुनरीक्षण के लिए MoEFCC की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज (CSCCC) ने शासकीय प्राथमिकताओं के साथ NDCs और SDG को संरेखित कर SAPCC के पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की है। व्यापक डेटा संग्रह, जलवायु प्रवृत्ति विश्लेषण और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता के विश्लेषण का कार्य पूर्ण हो चुका है। SAPCC पुनरीक्षण प्रक्रिया में एक अंतिम चरण के रूप में, सभी सम्बंधित विभागों के प्रतिनिधियों के साथ एक प्राथमिककरण कार्यशाला का आयोजन 25/02/2021 को किया गया ताकि प्रमुख अनुकूलन और शमन उपायों का चयन किया जा सके। इसके अलावा, पिछले SAPCC में प्रस्तावित गतिविधियों के कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित जानकारी भी एकत्रित की गई।

श्री सुधीर कुमार अग्रवाल, आईएफएस, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र ने कार्यशाला में भाग लेने तथा SAPCC के पुनरीक्षण हेतु डेटा उपलब्ध कराने के लिए सभी विभागों के प्रतिनिधियों का धन्यवाद व्यक्त किया। श्री एडविन कोएक, Counsellor, Energy and Climate Action, Delegation of the European Union to India ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के लिए राज्य कार्य योजना के पुनरीक्षण में छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने में प्रसन्नता व्यक्त की।

डॉ आशीष चतुर्वेदी, Director & Climate Change, GIZ India ने इस अवसर पर बताया कि GIZ इंडिया ने **SAPCC** के पहले संस्करण को तैयार करने में 18 राज्यों और MoEFCC द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार **SAPCC** के पुनरीक्षण में 7 राज्यों की सहायता की है। **SAPCC** के संशोधन में छत्तीसगढ़ आठवां राज्य है, जिसमें 2030 तक शमन और अनुकूलन गतिविधियों का विवरण शामिल किया है। कार्यशाला के प्रमुख वक्ता प्रो. डॉ. एन.एच. रविंद्रनाथ, Professor, Centre for Sustainable Technologies, Indian Institute of Science ने SAPCC के पुनरीक्षण प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख मुद्दों तथा वन क्षेत्र की संवेदनशीलता विश्लेषण के परिणाम पर प्रकाश डाला। उन्होंने MoEFCC दिशानिर्देशों के अनुसार नए प्रस्तावित टेम्पलेट और संरचना के बारे में संक्षेप में बताया। उन्होंने कहा कि शमन और अनुकूलन के अध्यायों में हमें प्रत्येक क्षेत्र में परियोजनाओं / कार्यक्रमों को अधिक यथार्थवादी तरीके से प्राथमिकता देनी होगी।

छत्तीसगढ़ में देश के तीन चौथाई से अधिक लघु वनोपजों का संग्रहण

'द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (ट्राईफेड)' द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में देश में कुल संग्रहित लघु वनोपजों में से तीन चौथाई से अधिक अर्थात् 75.38 प्रतिशत लघु वनोजपों का संग्रहण छत्तीसगढ़ में हुआ है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अभी 23 मार्च तक देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 181 करोड़ 25 लाख रूपए की राशि के लघु वनोपजों की खरीदी की गई है। इसमें छत्तीसगढ़ में 136 करोड़ 63 लाख रूपए की राशि के लघु वनोपजों की खरीदी शामिल है।

राज्य में वर्तमान में विगत अक्टूबर से अब तक लगभग 6 माह की अवधि में 32 करोड़ 63 लाख रूपए की राशि के एक लाख 20 हजार 665 क्विंटल लघु वनोपजों का संग्रहण किया गया है। इनमें 6 करोड़ 64 लाख रूपए की राशि के 39 हजार 84 क्विंटल बहेड़ा, 10 करोड़ 77 लाख रूपए की राशि के 29 हजार 921 क्विंटल इमली (बीज सहित) तथा 3 करोड़ 43 लाख रूपए की राशि के 22 हजार 836 क्विंटल हर्रा का संग्रहण हो चुका है। इसी तरह 4 करोड़ 15 लाख रूपए की राशि के 10 हजार 376 गिलोय, 2 करोड़ 59 लाख रूपए की राशि के 7 हजार 392 क्विंटल कालमेघ तथा 78 लाख रूपए की राशि के 345 क्विंटल शहद का संग्रहण किया गया है।

इस दौरान माहुल पत्ता, नागरमोथा, भेलवा, बहेड़ा कचरिया, धवई फूल (सूखा), हर्रा कचरिया, पुवाड़ (चरोटा), बेल गुदा, सतावर (सूखा), कुसुम बीज, फुल झाड़ू, रंगीनी लाख, वन तुलसी, फूल इमली, जामुन बीज (सूखा), वन जीरा, इमली बीज, आंवला बीज रहित, कुसुमी लाख कुल्लू गोंद, महुआ बीज, करंज बीज तथा बायबडिंग का संग्रहण हुआ है। इसके अलावा पाताल कुम्हड़ा (बेदारी कंद), तिखुर, सवई घास, कोरिया छाल, छिन्द घास, आंवला (कच्चा), कांटा झाड़ू, कुटज छाल, अडुसा पत्ता, इन्द्रजौ बीज, सफेद मुसली, पलाश फुल, काली मूसली, कोरिया बीज, बैचांदी, बेल (कच्चा), बीहन लाख-कुसमी तथा बीहन लाख-रंगीनी का भी संग्रहण किया गया है। इनमें से एक करोड़ 78 लाख रूपए की राशि के एक हजार 187 क्विंटल पाताल कुम्हड़ा का संग्रहण हो चुका है। उल्लेखनीय है कि लघु वनोपज के संग्रहण से राज्य में ग्रामीण एवं जनजातिय क्षेत्रों में अतिरिक्त आय एवं आजीविका के नवीन क्षेत्रों का सृजन हो रहा है।

(स्त्रोत – http://dprcg.gov.in)

नरवा विकास योजना – वन क्षेत्रों में भू–जल संरक्षण के बड़े तादाद में हो रहे कार्य

राज्य शासन की महत्वाकांक्षी 'नरवा विकास योजना' के तहत प्रदेश के वन क्षेत्रों में स्थित नालों मे कैम्पा मद की वार्षिक कार्ययोजना 2019–20 के तहत 12 लाख 9 हजार 485 संरचनाओं का निर्माण जारी है। इनमें से अब तक लगभग 11 लाख संरचनाओं का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इनका निर्माण 155 करोड़ रूपए की राशि से किया जा रहा है।

राज्य में इसके तहत 155 करोड़ रूपए की राशि से 01 हजार 766 किलोमीटर लंबाई के विभिन्न नालों में भू–जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। इन संरचनाओं के पूर्ण होने पर 4 लाख 65 हजार 172 हेक्टेयर भूमि उपचारित होगी। इसमें वन क्षेत्रों के नालों में भू–जल संरक्षण कार्य के लिए लूज बोल्डर चेकडेम, बोल्डर चेकडेम, ब्रशवुड चेकडेम, कंटूर ट्रेंच, परकोलेशन टैंक, अर्दन डेम, चेकडेम, एनीकट, स्टापडेम तथा गेबियन आदि संरचनाओं का काफी तादाद में निर्माण किया जा रहा है। इससे एक ओर वन भूमि के क्षरण को रोका जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर जल भंडार में वृद्धि की जा सकेगी। वन क्षेत्रों में जल भंडार की पर्याप्त उपलब्धता से वन्य जीवों को उनके रहवास क्षेत्र में ही चारा–पानी उपलब्ध होगा, जिससे वे आबादी क्षेत्रों की ओर आकर्षित नहीं होंगे। इसके साथ ही वनों के आसपास के ग्रामीणों तथा कृषकों को पेयजल तथा सिंचाई के साधन विकसित करने में मदद मिलेगी।

(स्त्रोत – http://dprcg.gov.in)

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'गोधन न्याय योजना' को मिला स्कॉच गोल्ड अवार्ड

छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी 'गोधन न्याय योजना' को पर्यावरण संरक्षण और सतत् विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए 'स्कॉच गोल्ड अवार्ड' से सम्मानित किया गया है। गोधन न्याय योजना का क्रियान्वयन सुराजी गांव योजना के तहत कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सहाकारिता विभाग सहित विभिन्न विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौठानों में 15 मार्च 2021 तक 1 लाख 18 हजार 611 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किया गया है, जिसमें से 83 हजार 900 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का विक्रय भी किया जा चुका है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से प्रदेश के 1 लाख 62 हजार 497 पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं। जिनमें 70 हजार 299 भूमिहीन ग्रामीण शामिल हैं। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों में 44.55 प्रतिशत महिलाएं हैं। गोधन न्याय योजना में अब तक पशुपालकों से 44 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है।

(स्त्रोत – http://dprcg.gov.in)

क्या आप जानते हैं ?

To fulfil the GoI commitment of cleaner future an additional capital infusion of Rs 1,000 crores allocated to Solar Energy Corporation of India and 1,500 crores to Indian Renewable Energy Development Agency
moefcc
moefcc
moefccgoi
moef.gov.in

DID YOU KNOW?
Why conserving Snakes is important for the ecosystem?
Snakes play a crucial role in ecosystem functioning.
They are friends of farmers because snakes control a large percentage of rodents.
Venoms of many species of snakes are used for the preparation of life-saving drugs.
Some species of snakes are ecological-indicators, and the presence of the species indicates undisturbed habitat.
moefcc
moefcc
moefccgoi
moef.gov.in

To manage faecal sludge and wastewater treatment, source segregation of garbage, reduction in single-use plastic, reduction in air pollution the amount of Rs. 1,41,678 crores allocated in Budget 2021.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (25 जनवरी, 2021) को जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित किया जिसमे उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक भारत 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को लक्षित कर रहा है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ''जलवायु अनुकूलन'' आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और यह भारत के विकास के प्रयासों का एक प्रमुख अंश है।

अपने संबोधन में उन्होंने कहा, ''हमने खुद से वादा किया है कि : हम सिर्फ हमारे पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें पार कर लेंगे ; हम न केवल पर्यावरणीय गिरावट को रोकेंगे, बल्कि इसे उलट देंगे ; और हम न केवल नई क्षमताओं का निर्माण करेंगे बल्कि उन्हें वैश्विक स्तर पर अच्छा बनाने के लिए एक एजेंट बनाएंगे।''

उन्होंने यह भी कहा कि भारत एलईडी रोशनी को बढ़ावा दे रहा है और सालाना 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की बचत कर रहा है।

(स्त्रोत – https://www.pib.gov.in/)

केरल के एनएस राजप्पन जो प्रतिदिन वेम्बनाड झील की सफाई करते हैं

69 वर्षीय एनएस राजप्पन पिछले छह साल से झील की सफाई के मिशन पर हैं। वे पैरों से विकलांग होने के कारण नहीं चल सकते हैं। वे घूमने के लिए अपने हाथों का उपयोग करते हैं। वह केरल के कोट्टायम जिले में मंजनिक्कारा में रहते हैं।

पिछले छह साल से, राजप्पन कोट्टायम जिले के वेम्बनाड झील और कुमारकोम की अन्य धाराओं से प्लास्टिक कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। वह एक छोटे से नाव को किराए पर लेते हैं और रोज सुबह प्लास्टिक इकट्ठा करने के लिए निकल जाते हैं। वे नाव चलाने के लिए चप्पू का उपयोग करते हैं। वह मुख्य रूप से प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा करते हैं जिन्हें पानी में फेंक दिया गया है।

विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर भारत को मिला पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केन्द्र

विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर और भारत की आर्द्रभूमियों के संरक्षण, बहाली और प्रबंधन की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता के क्रम में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो ने मंत्रालय के तहत आने वाले संस्थान राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केन्द्र (एनसीएससीएम), चेन्नई के भाग के रूप में आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केन्द्र (सीडब्ल्यूसीएम) की स्थापना की घोषणा की है। इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से एनसीएससीएम, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों और आर्द्रभूमि विभाग के ज्ञान भागीदारों ने भाग लिया था।

पर्यावरण राज्य मंत्री ने इस अवसर पर पर्यावरण से जुड़ी विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने में आर्द्रभूमियों के महत्व को रेखांकित किया। श्री सुप्रियो ने कहा, ''आज शुरू किए गए इस प्रतिबद्ध केन्द्र में विशेष शोध जरूरतों और जानकारियों में कमी का समाधान निकाला जाएगा। साथ ही आर्द्रभूमियों के संरक्षण, प्रबंधन और उचित उपयोग के लिए एकीकृत रणनीतियों के उपयोग में सहयोग लिया जाएगा।''

भारत में लगभग 4.6 प्रतिशत जमीन आर्द्रभूमि है, जिनका क्षेत्रफल 1.526 करोड़ हेक्टेयर है और 42 स्थान अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों (रामसर साइट्स) के रूप में नामित हैं, जिनका क्षेत्रफल 10.8 लाख हेक्टेयर है। 2 फरवरी 2021 को, 1971 में रामसर में रामसर समझौते पर हस्ताक्षर की 50वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है, इसी दिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है।

केन्द्र उपयुक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्टीय एजेंसियों के साथ भागीदारी और नेटवर्क विकसित करने में मदद करेगा। डब्ल्यूसीएम एक ज्ञान के केन्द्र के रूप में काम करेगा और राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के आर्द्रभूमि प्राधिकरणों, आर्द्रभूमि के उपयोगकर्ताओं, प्रबंधकों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और प्रैक्टिसनर्स के बीच विचारों के आदान प्रदान को सक्षम बनाएगा। केन्द्र उनके संरक्षण के लिए नीति और नियामकीय रूप रेखाओं के निर्माण व उनके कार्यान्वयन, प्रबंधन योजना, निगरानी और लक्षित अध्ययन में भी सहयोग करेगा।

(स्त्रोत – https://www.pib.gov.in/)

समाचार शीर्षक

कलेक्टर ने जल संरक्षण एवं संवर्धन में सूरजपुर को देश के उत्कृष्ट जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर पूरी टीम को दी बधाई

सूरजपुर जिला ईस्ट अंडरवाटर कन्जर्वेशन कैटेगिरी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित

यह उपलब्धि सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है- रणबीर शर्मा

श्रमबिन्दु / सूरजपुर

भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रालय की ओर से सूरजपुर जिले को जल संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में किये गये कार्यों के लिए देष के सर्वश्रेष्ठ जिलों में प्रथम स्थान मिला हैं। कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा एवं जिला पंचायत सीईओ श्री आकाश छिकारा के मार्गदर्शन में यह सामूहिक प्रयास से उपलब्धि प्राप्त हुई हैं। केन्द्र सरकार के जलशक्ति मंत्रालय द्वारा जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जिले को वर्ष 2019 का नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया। इसमें सूरजपुर जिले को ईस्ट अण्डर वाटर कन्जर्वेशन कैटेगरी पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। विगत 22 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा पुरस्कार की घोषणा की गई थी। द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त करने का प्रषस्ति पत्र आज जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ हैं।

इस उपलब्धि पर कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने कहा कि यह हमारे सामूहिक प्रयास का प्रतिफल हैं। इससे हमें और अच्छा कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त हुई हैं। आने वाले समय में जल संवर्धन एवं संरक्षण सहित अन्य क्षेत्रों में भी जिले के विकास के लिए बेहतर प्रयास किया जायेगा। कलेक्टर ने पूरी टीम को बधाई दी हैं। जिला पंचायत सीईओ श्री आकाश

छिकारा ने इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि वर्तमान में जल संरक्षण हेतु एनजीबीबी के नरवा परियोजना के अंतर्गत जिले में 64 नालों का विकास किया जा रहा है, जिसमें सिंचाई के लिए जल उपलब्धता बढ़ेगी व जल स्तर में भी वृद्धि होगी।

इन उपलब्धियों पर हुआ है जिले का चयन-

ज्ञात हो कि जिले में जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण कार्य कराए गए हैं जिससे कि सिंचाई व्यवस्था के साथ-साथ लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है साथ ही जल के स्तर में भी वृद्धि हुई है। जिले में लगभग एक लाख 48 हजार 32 हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है। विभिन्न विभाग एवं मनरेगा के तहत कुछ नाले के स्ट्रक्चर तैयार कर जायें संभव किया गया है। मनरेगा के तहत लगभग 5 हजार 665 स्ट्रक्चर तैयार किया गया, जिससे की लगभग 15199.8 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचित करने की संभावना बढ़ गई हैं। जिसमें कूआ, तालाब, बांध इत्यादि के कार्य कराए गए हैं। सिंचाई और जल स्तर में वृद्धि करने हेतु विभिन्न स्ट्रक्चर तैयार किया गया।

ग्रामों में बिजली न होने के बावजूद केडा के द्वारा लगभग 2237 सोलर पैनल एवं पंप लगाया गया जो वर्षा के सही समय पर न होने से सिंचाई हेतु किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है। जिले में ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए लगभग 2079 विभिन्न स्ट्रक्चर तैयार किये गए जैसे कि गली प्लग, एलबीसीडी गैबीआन स्ट्रक्चर परकोलेषन टैंक, रिचार्ज पिट इत्यादि। यह सभी स्ट्रक्चर तैयार करने से जिले में 156910 क्यूब मीटर जल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है।

जिले में जल स्तर वृद्धि के संदर्भ में लगभग 3120 पक्के शासकीय बिल्डिंग में रैन वाटर हार्वेस्टिंग लगाया गया तथा लगभग 9695 नलकूप के सामने सोक पीट का निर्माण किया गया है। जिले में वेस्ट वाटर को रीयूज करने हेतु विभिन्न स्कूलों एवं छात्रावासों में वेस्ट वाटर का उपयोग कर लगभग 383 किचन गार्डन बनाया गया है, जिससे की स्कूलों और छात्रावासों में ताजी सब्जियां उपलब्ध हुई हैं। इसके साथ ही माइन वाटर यूटिलाइजेशन से लगभग 19189 केएलडी वाटर उपलब्ध कराया गया जिससे की लगभग 20 हजार किसान लाभान्वित हुए हैं और 430 हेक्टेयर में सिचाई व्यवस्था कराई गई है। केनापरा में बोटिंग शुरू करवा कर लाइवलीहुड कार्यक्रम की तैयारी की गई जिसमें 156 हितग्राहियों को आजीविका कार्य से जोड़ते हुए उन्हें आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाया गया और जल संवर्धन की दिषा में एक अनूठा प्रयास जिला प्रषासन सूरजपुर ने किया है।

ग्लोबल वार्मिंग से जहरीली हो रहीं मछलियां

दुनिया के एक अरब लोगों का प्राथमिक आहार समुद्री जीव हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस आबादी के सामने खान-पान की समस्या खड़ी होती नजर आ रही है। अमेरिका के नेशनल ओशिएनिक एंड एटमोसफेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के शोधकर्ताओं के मुताबिक लगातार बढ़ते समुद्री तापमान से समुद्र में बड़ी मात्रा में शैवाल उग गए हैं। यह समुद्र में जहरीले रसायनों का उत्सर्जन कर रहे हैं जो मछलियों के जरिए इंसानों के शरीर में जा रहा है। इससे उनकी सेहत पर खतरा मंडरा रहा है।

अल नीनो असर का प्रभाव

प्रशांत महासागर के तापमान और वायुमंडल में आए बदलाव को अल नीनो असर कहा जाता है। इसमें समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से कुछ अधिक हो जाता है। इसी के कारण समुद्र में रसायन बढ़ रहे हैं।

भविष्य भी खतरे में

2100 तक धरती का औसत तापमान 3.5 डिग्री होने की आशंका है। इसके चलते समुद्र में इस रसायन की मात्रा भी बढ़ेगी। ऐसे में समुद्री भोजन में भारी कमी होगी।

घातक रसायन

सूडा-नित्रिया शैवाल से डोमोइक एसिड निकलता है। यह रसायन केकड़ा, घोंघा मछलियों और अन्य सीप वाली मछलियों में जमा हो रहा है। इन्हें खाने से इंसानों को दिल का दौरा, भूलने की बिमारी और मौत तक हो सकती है।

घटी कीमत

मछलियों में रसायन होने के मामले सामने आने पर 2015 में अमेरिका के पश्चिमी तट पर डंगीनेस केकड़े की कीमत 100 डॉलर कम हो गई थी।

बढ़ी लागत

जिन तटीय देशों में समुद्री जीवों की खपत ज्यादा है वहां इनकी जांच में खर्च बढ़ गया है।

अन्य जीवों पर भी संकट

छोटी मछलियों को खाने वाली बड़ी मछलियां भी इस रसायन का शिकार हो रही हैं। यह बड़ी संख्या में डॉल्फिन और व्हेल जैसे समुद्री जीवों की जान ले चुका है।

10 करोड़ मेट्रिक टन : दुनिया में सालाना पकड़ी जाने वाली मछली की मात्रा

892 इंसानों द्वारा खाई जाने वाली मछलियों की प्रजातियां

2021 होगा सबसे ज्यादा गर्म साल

वातावरण में 300 साल की तुलना में 50% ज्यादा बढ़ी कार्बन डाइऑक्साइड

एजेंसी | लंदन

हमारे पर्यावरण में कॉर्बन-डाइऑक्साइड (सीओ2) गैस का उत्सर्जन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसे लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि 2021 अब तक का सबसे ज्यादा गर्म साल हो सकता है। एक अध्ययन में रिसर्चर्स ने बताया कि सीओ2 स्तर इस साल के अंत तक 18वीं सदी (करीब 300 साल पहले) में हुई औद्योगिक क्रांति के पहले हो रहे मानव जनित कॉर्बन उत्सर्जन के स्तर से 50% ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि सीओ2 का स्तर 18वीं सदी के स्तर से डेढ़ गुना के करीब बढ़ेगा। हालिया स्टडी में अमेरिका और ब्रिटेन के रिसर्चर्स ने हवाई और बर्फीले इलाके के सीओ2 डेटा का विश्लेषण किया है। इसमें पाया कि 1750-1800 में सीओ2 का औसत स्तर 278 पार्ट्स प्रति मिलियन (पीपीएम) था। वहीं मार्च 2021 में हमारे वायुमंडल में सीओ2 का स्तर 417.14 पीपीएम तक पहुंच गया।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि मई तक कॉर्बन उत्सर्जन और बढ़ेगा। साथ ही, 2021 में इसका औसत 419.5 पीपीएम पर पहुंच जाएगा। विश्लेषण से पता चला कि 1760 के आसपास शुरू हुआ कार्बन-डाइऑक्साइड मार्च 2021 तक एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साइमन लुईस ने कहा कि वायुमंडल में कार्बन-डाइऑक्साइड की मात्रा को 25% बढ़ने में 200 साल लगा, जबकि औद्योगिक क्रांति के पूर्व के स्तर से यह सिर्फ 30 साल में 50% से ऊपर पहुंच गया। यह नाटकीय परिवर्तन एक मानव उल्कापिंड पृथ्वी की तरह है।

सम्पादक मंडल

- श्री सुधीर कुमार अग्रवाल (मुख्य संपादक)
- डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव
- श्री अभिनव अग्रहरी
- श्री राजेश टोप्पो

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ

अरण्य भवन, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर–19

नवा रायपुर, छत्तीसगढ

ईमेल : chhattisgarh.sccc@gmail.com

वेबसाइट : www.cgclimatechange.com